भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2292

02 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

नवरत्न कंपनियों का निजीकरण

2292. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन नवरत्न कंपनियों के नाम और ब्यौरा क्या है, जिन्हें निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है अथवा देने की योजना है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इन नवरत्न कंपनी-वार को लाभ/हानि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी नवरत्न-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नवरत्न कंपनियों के ऐसे निजीकरण से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है;

(घ) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल को भी किसी निजी कंपनी को आवंटित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे किस अवधि के लिए आवंटित किया जाना है और किस मूल्य पर बेचा गया है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ निजीकरण संबंधी नॉर्म्स पर चर्चा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य सरकार संयंत्र को निजी कंपनियों को बेचने पर सहमत हुई और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा/क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के अनुसार मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मुख्यतः रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों वाले पीएसई पर व्यवहार्यता के आधार पर निजीकरण हेतु विचार किया जाएगा अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद किए जाने पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय

इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में निर्णय लिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान आरआईएनएल के लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	**2020-21#**	**2021-22**	**2022-23##**
प्रचालनों से राजस्व	18,080.88	28,359.35	22,809.40
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	-1,035.96	941.58	-3,236.46
कर-पश्चात् लाभ (पीएटी)	-789.10	913.19	-2,858.74

वर्ष 2020-21 पुनर्घोषित कर-पूर्व लाभ (-)1259.02 करोड़ रुपये और कर-पश्चात् लाभ (-)1012.16 करोड़ रुपये।

सीएंडएजी लेखा परीक्षा के अधीन अनंतिम।

(घ): नई पीएसई नीति के अनुसार, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से आरआईएनएल की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में आरआईएनएल की हिस्सेदारी सहित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में भारत सरकार की शेयरधारिता के 100% विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

(ङ) और (च): राज्य सरकार की आरआईएनएल में कोई इक्विटी नहीं है। हालांकि, आवश्यकता होने पर विशिष्ट मामलों में राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है और जिन मामलों में उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनमें उनकी सहायता भी माँगी जाती है।

****